भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2293
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2025

बीएसएनएल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2293. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या संचार **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा पर्याप्त राजस्व अर्जन में योगदान देने वाले कारकों का आकलन किया है और यदि हां, तो उक्त आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन आकलनों के निष्कर्ष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से बीएसएनएल के कार्यबल में 35 प्रतिशत की कटौती करने के निर्णय का समर्थन करते हैं और यदि हां, तो इस उपाय का औचित्य क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बीएसएनएल की वीआरएस पहल को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की पिछली वीआरएस पहल जैसी चुनौतियों, जो इसके वित्तीय निष्पादन में सुधार करने में विफल रही थीं, का सामना न करना पड़े; और

(घ) वीआरएस योजना पहल के संबंध में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ द्वारा उठाई गई चिंताओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनकी शिकायतों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने की योजना है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) सरकार ने वर्ष 2019 में संप्रभु गारंटी बॉण्ड के साथ-साथ वीआरएस के माध्यम से ऋण के पुनर्गठन द्वारा बीएसएनएल की प्रचालन लागत में कटौती करने के लिए प्रथम पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया था। वर्ष 2019 में वीआरएस के कार्यान्वयन के बाद, बीएसएनएल की

कर्मचारी लागत में 51 प्रतिशत की कमी आई। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप बीएसएनएल ने वर्ष 2020-21 से प्रचालनगत लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया।

4जी सेवाओं के रॉलआउट में विलम्ब के साथ-साथ मोबाइल सेग्मेंट में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बीएसएनएल का राजस्व प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर पहल के तहत बीएसएनएल ने 1 लाख 4जी साइट के लिए क्रय आदेश दिया। दिनांक 05.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल 83,629 4जी साइटों को संस्थापित किया गया है जिनमें से 74,123 साइटें ऑन एयर हैं।

वर्तमान में बीएसएनएल में वीआरएस हेतु इस विभाग में किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

*****